

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2021—आषाढ़ 11, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अप्रैल 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री अभिषेक शर्मा, भा.प्र.से. (2018), अनुविभागीय अधिकारी, कटघोरा, जिला-कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सहायक कलेक्टर, कोरबा के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 मई 2021

संशोधन

क्रमांक एफ 04-05/2019/चौबीस.—छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम-2019, दिनांक 29 नवंबर, 2019 को साधारण राजपत्र प्रकाशित किया गया था. राज्य शासन अब छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम, 2019 में निम्न संशोधन करता है :—

कण्डिका-8 : पत्रकार कल्याण सहायता राशि से संचार प्रतिनिधि अथवा आश्रित परिवार के सदस्यों को एक वर्ष में न्यूनतम 10 हजार और अधिकतम 2.00 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा सकेगी. आकस्मिक मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता रुपए 5.00 लाख होगी.

कण्डिका-8.1 : छत्तीसगढ़ संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति की अनुशंसा पर आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क अधिकतम राशि रुपये 2.00 लाख रुपए तथा आकस्मिक मृत्यु की दशा में रुपए 5.00 लाख तक की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर सकेंगे.

कण्डिका-8.4 : आर्थिक सहायता की वित्तीय सीमा

1. पत्रकार की मृत्यु
 - (अ) एकमुश्त अधिकतम राशि रु. 5.00 लाख

अथवा

- (ब) अधिकतम राशि रु. 2.50 लाख तथा रु. 7000/- प्रतिमाह पेंशन आगामी 3 वर्ष तक वैध उत्तराधिकारी को

अथवा

- (स) अधिकतम 2 बच्चों को रु. 1500 प्रतिमाह की ट्यूशन फीस कक्षा दसवीं तक रु. 2500/- प्रतिमाह कक्षा बारहवीं तक तथा स्नातक शिक्षा (03 वर्ष के लिए) के लिए प्रतिमाह रु. 3500/- आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि संबंधित बच्चा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ कक्षा उत्तीर्ण कर रहा हो.

अथवा

- (द) अधिकतम राशि रुपए 2.50 लाख की तत्कालिक सहायता एवं आश्रित एक बच्चे के उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 मार्च 2021

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—राज्य शासन एतद्वारा चीफ कन्ट्रोलर ऑफ माइन्स, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के परिपत्र क्रमांक 2/2010, दिनांक 06-04-2010 के पैरा-2 के बिन्दु क्रमांक-2 एवं पत्र दिनांक 21-09-2011 तथा भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 08-10-2014 एवं खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम, 12 के अनुपालन में Differential Global Positioning System (डीजीपीएस) का उपयोग करते हुए खनिज कोयला को छोड़कर समस्त खनिजों के खनिज रियायतों के

सीमाओं में Pricise Boundary Pillar की स्थापना कर सर्वेक्षण करने के लिए नीचे तालिका के कॉलम नंबर-02 में दर्शित संस्थानों को नवीन अधिमान्यता/नवीनीकरण प्रदान करता है :—

क्र. (1)	आवेदित एजेंसी का नाम एवं पता (2)	रिमार्क (3)
	नवीन अधिमान्यता हेतु अनुशंसित एजेन्सी —	
01.	मेसर्स मार्बल जियोस्पेशल सॉल्युशन प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना.	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनिज रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.
02.	मेसर्स सुबुद्धि टेक्नोइंजिनियरस् प्रायवेट लिमिटेड, भूवनेश्वर, उड़ीसा.	
03.	मेसर्स टेकडेटम इंफोसर्विस प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना.	
	नवकरण हेतु अनुशंसित एजेन्सी —	
04.	मेसर्स सोहम फेरो मैंगनिज प्रायवेट लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र.	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनिज रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.

उपर्युक्त तालिका के सरल क्रमांक-01 से 03 तक संस्थानों को डीजीपीएस सर्वे कार्य किये जाने हेतु नवीन अधिमान्यता प्रदान किये जाने एवं सरल क्रमांक-04 मेसर्स सोहम फेरो मैंगनीज प्रायवेट लिमिटेड को विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-11-2017 द्वारा 03 वर्ष की अवधि के लिये सशर्त प्रदान की गई अधिमान्यता की अवधि दिनांक 09-11-2020 को समाप्त हो गई है. अतएव राज्य शासन, एतद्वारा अधिमान्यता का नवकरण दिनांक 09-11-2020 से आगामी 03 वर्ष के लिये नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती है.

2. अधिमान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए निम्नानुसार शर्तें निर्धारित की गई है :—

- Each corner of the lease area shall have a boundary pillar (corner pillar).
- There shall be erected intermediate boundary pillars between the corner pillars in such a way that each pillar is visible from the adjacent pillar located on either side of it:
- The distance between two adjacent pillars shall not be more than fifty meters;
- The pillar shall be of square pyramidal frustum shaped above the surface and cuboid shaped below the surface;
- Each pillars shall be of reinforced cement concrete;
- The corner pillar shall have a base of 0.3m x 0.3m and height of 1.30m of which 0.70m shall be above ground level and 0.60m below the ground;
- The intermediate pillars shall have a base of 0.25m x 0.25m and height of 1.0m of which 0.70m shall be above ground level and 0.30m below the ground;
- All pillars shall be painted in yellow colour and the top ten centimeters in red colour by enamel paint and shall be grouted with cement concrete.
- On all corner pillars, distance and bearing to the forward and backward pillars and latitude and longitude shall be marked.
- Each pillar shall have serial number in a clockwise direction and the number shall be engraved on the pillars;
- The number of pillars shall be the numbers of the individual pillar upon the total number of pillars in the lease;

12. The tip of all the corner boundary pillars shall be a square of 15 centimeter on which a permanent circle of 10 centimeter diameter shall be drawn by paint or engraved and the actual boundary point shall be intersection of two diameters drawn at 90 degrees.
 13. The lease boundary survey shall be accurate within such limits of error as the Control General, Indian Bureau of Mines may specify in this behalf;
 14. The location and number of the pillars shall also be shown in the surface and other plans maintained by the lessee: and
 15. In case of forest area within the lease, the size and construction and colour of the boundary pillars shall be as per the norms specified by the Forest Department in this behalf.
 16. The Survey Agency shall be responsible for the accuracy of the data collected during Survey.
 17. Coordinates of boundary pillars shall be established in the world Geodetic System 1984 (WGS-84) Datum.
 18. डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त संस्थान एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जायेगा. किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होने पर राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा.
 19. डीजीपीएस सर्वे कार्य के गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की कार्य संबंधी शिकायत पाये जाने पर जांच उपरान्त राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि उक्त अधिकृत एजेंसी की मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है.
 20. डीजीपीएस सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा.
 21. राज्य शासन द्वारा जारी यह अधिमान्यता 03 वर्ष के लिए होगी. समयावधि समाप्ति से 03 माह पूर्व अधिकृत एजेंसी नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा.
3. यह अधिमान्यता/नवकरण अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए ही मान्य होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी. सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31 मार्च 2021

क्रमांक एफ 1-7/2020/रोज.वि./42.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य सेवा परीक्षा-2018 के अनुपूरक सूची से चयनित सुश्री श्वेता वर्मा/पिता श्री महेश कुमार वर्मा, ई-9, सी.एस.पी.टी.सी.एल. कॉलोनी, खेदामारा जामुल, दुर्ग को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2005 के तहत रोजगार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर वेतनमान रुपये मैट्रिक्स लेवल-12 (ग्रेड पे-5400/-) पर नियुक्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र, जगदलपुर में पदस्थ करता है.

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

- (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, दिनांक 28-07-2020 के प्रावधान अनुसार चयनित अभ्यर्थी को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया है। उक्त अवधि में वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28-07-2020 के प्रावधान अनुसार नियत स्टापपेण्ड देय होगा तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब अभ्यर्थी का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जावेगा।
- (ख) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- (ग) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- (घ) चयनित प्रत्याशियों को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (ङ) चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सकीय (मेडिकल) योग्यता प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- (च) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। अतः यदि संबंधित अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन में पुलिस अधीक्षक द्वारा विपरीत टिप्पणी अंकित की जाती है, तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी। इस संबंध में संबंधित को कार्यभार ग्रहण के समय अंडरटेकिंग, नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (छ) चयनित प्रत्याशियों की वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संसूचित प्रवीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा।

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, उप-सचिव।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 मई 2021

क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधात हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-10-2019 के द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य की “औद्योगिक नीति-2019-24” में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

- (एक) उक्त अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक-15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक-2 के कॉलम-2 में वर्णित “स्थायी पूंजी लागत अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों हेतु)” को “स्थायी पूंजी लागत अनुदान (सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों हेतु)” पढ़ा जावे।

- (दो) उक्त अधिसूचना द्वारा जारी औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-3 के अंतर्गत प्राथमिकता उद्योगों की सूची में (अ) वर्गीकरण के आधार पर-के “अनुक्रमांक-10” में वर्णित “मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्वूपमेंट” को “विलोपित” करते हुए इसे परिशिष्ट-2 के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में “अनुक्रमांक-18” पर “मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्वूपमेंट” का समावेश किया जाता है।
- (तीन) उक्त अधिसूचना द्वारा जारी औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-2 के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में “अनुक्रमांक-18” के पश्चात् अनुक्रमांक 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एवं 27 के रूप में निम्नानुसार नवीन वस्तुओं का समावेश किया जाता है :—
- | | | |
|---------------|---|--|
| अनुक्रमांक-19 | — | मेडिकल ग्रेड आक्सीजन गैस (लिक्विड एवं गैसीयस माध्यम से) |
| अनुक्रमांक-20 | — | आक्सीजन गैस सिलेण्डर |
| अनुक्रमांक-21 | — | आक्सीजन कन्सनट्रेटर |
| अनुक्रमांक-22 | — | क्रायोजेनिक गैस टैंकर |
| अनुक्रमांक-23 | — | फेस मास्क, नॉन रिब्रिडर मास्क, आक्सीजन फ्लो मीटर, नेसल केन्यूला आदि |
| अनुक्रमांक-24 | — | नॉन इन्वेसीव वेन्टिलेटर, इन्वेसीव वेन्टिलेटर, |
| अनुक्रमांक-25 | — | सर्जिकल दस्ताने, पी पी ई किट, ओवर ऑल बॉडी प्रोटेक्टर, |
| अनुक्रमांक-26 | — | कोविड व अन्य संक्रामक बीमारियों के टेस्ट में उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण, फॉर्मास्युटिकल्स, बीमारियों से संबंधित से संबंधित स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी उपकरण एवं दवाएं. |
| अनुक्रमांक-27 | — | टीका बनाने के उपकरण, RT-PCR Test, True-nat Test, Antigen Test के लिए आवश्यक Reagents. |

उपरोक्त सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जावेंगे.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 मई 2021

क्रमांक एफ 20-47/2013/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधात हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-03-2015 द्वारा जारी “छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015” में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

- (एक) उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 की कंडिका 2.5 की उप कंडिका क्रमांक 2.5.7 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

कंडिका क्र. 2.5.7 - अविकसित भूमि के आबंटन की दरें — ऐसी भूमि, जो औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित की गई है तथा जिस पर सर्वे एवं डिमाकेशन को छोड़कर अन्य कोई विकास व्यय नहीं किया गया है, को अविकसित भूमि माना जायेगा. ऐसी निजी भूमि अर्जन के वर्तमान मूल्य/गाईड लाईन मूल्य पर किये गये व्यय में 10 प्रतिशत राशि एवं भूमि की प्रब्याजि निर्धारित की जायेगी. उस क्षेत्र में समीपस्थ निजी भूमि के अर्जन मूल्य/गाईड लाईन मूल्य में से जो भी अधिक हो, में 10 प्रतिशत राशि एवं 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि जोड़ कर भू प्रब्याजि निर्धारित की जायेगी ऐसी अविकसित भूमि का आबंटन विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुमोदन से ही हो सकेगा.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को हस्तारित शासकीय भूमि के आबंटन के मामले में होने की दशा में भी आबंटन दिनांक के वित्तीय वर्ष हेतु उस क्षेत्र में समीपस्थ निजी भूमि के गाईड लाईन मूल्य के 150 प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत सेवा शुल्क (यथा लागू कर अतिरिक्त) की राशि जोड़ कर भू प्रब्याजि निर्धारित की जायेगी ऐसी अविकसित भूमि का आबंटन विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुमोदन से ही हो सकेगा.

ऐसी अविकसित भूमि का वार्षिक भू-भाटक निर्धारित भू-प्रब्याजि का 3 प्रतिशत की दर से लिया जायेगा एवं इस भूमि पर संधारण शुल्क नहीं लिया जायेगा.

परन्तु, भविष्य में यदि ऐसे अविकसित क्षेत्र में राज्य शासन/निगम कोई विकास कार्य प्रारंभ करता है तो पूर्व के भूमि आबंटन के प्रकरणों में भी औद्योगिक इकाईयों को राज्य शासन/सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित दरों पर भू-भाटक तथा संधारण शुल्क देना होगा।

परन्तु, यदि किसी भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ है, चाहे उस क्षेत्र में विकास पूर्ण नहीं हुआ है तो भी विकसित भूमि मानकर तदनुसार निर्धारित दरों से भू-प्रब्याजि, भू-भाटक तथा यथा निर्धारित संधारण शुल्क लिया जायेगा।

कंडिका के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

- (दो) उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 की कंडिका क्रमांक 2.13 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—
- कंडिका क्र. 2.13 - फ्रीहोल्ड पर भूमि** — जिन प्रकरणों में औद्योगिक क्षेत्र में/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर/लैंड बैंक से आबंटित भूमि में “गत् 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया हो” तथा प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग केवल पट्टाभिलेख में उल्लेखित एवं निर्धारित मूल प्रयोजन के लिए एवं आवेदन दिनांक पर लीज डीड निरस्त स्थिति में न हो, केवल ऐसे ही प्रकरणों में इस सुविधा का लाभ उठाने की पात्रता पट्टाधिकारी को होगी। यह भी कि आवेदनकर्ता को “4 हेक्टेयर या 10 एकड़ तक भूमि आबंटित हो” तथा उसके विरुद्ध शासन के किसी विभाग/सक्षम आबंटन प्राधिकारी द्वारा पट्टाभिलेख के प्रावधानों के तहत कोई कार्यवाही अपेक्षित/प्रचलित न हो, को आबंटित भूमि विभाग द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन फ्रीहोल्ड लेने की पात्रता होगी, किन्तु वह प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग केवल पट्टाभिलेख में उल्लेखित एवं निर्धारित मूल प्रयोजन के लिए ही कर सकेगा तथा वह भूमि केवल औद्योगिक प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रु. 10,000 के सांकेतिक दर पर हस्तांतरित की जा सकेगी, जिसके लिये हस्तांतरण हेतु आपसी अनुबंध के तीन माह के भीतर प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी। पट्टे की अन्य शर्तों को तदनुसार ही संशोधित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रावधान का पालन न किये जाने की स्थिति में मूल आबंटन प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह नियमों के अनुसार यथा आवश्यक कार्यवाही प्रचलित कर सकेगा एवं सक्षम आदेश पारित कर सकेगा, जिसमें उक्त प्रयोजन के लिए अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त जमा कराई गई राशि राजसात भी की जा सकेगी।

- (तीन) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 की कंडिका 3.1.2 की उप कंडिका क्रमांक 3.1.2.2 के चौथे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :—

कंडिका क्र. 3.1.2.2 - आबंटित भूमि का पूर्ण उपयोग करना — परन्तु, औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित, यदि अतिशेष भूमि पृथक औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए आबंटन योग्य है, अर्थात् उसमें पृथक से मार्ग उपलब्ध है, तो संबंधित आबंटि (मूल) द्वारा उसे आबंटित भूमि का आंशिक समर्पण किये जाने पर, आंशिक समर्पित भूमि नवीन इकाई की स्थापना हेतु संबंधित आबंटि द्वारा प्रस्तावित नये निवेशक के पक्ष में विभाग के आबंटन प्राधिकारी के समक्ष आंशिक समर्पण के पश्चात् नवीन आबंटि द्वारा प्रश्नाधीन आंशिक भूखण्ड हेतु आबंटन आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक पर संबंधित क्षेत्र हेतु निर्धारित/प्रचलित प्रब्याजी की 50 प्रतिशत की दर पर आबंटित की जा सकेगी, (रक्त संबंधी अंतरण के प्रावधान की कंडिका क्रमांक 3.4.1.2 में विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य विभाजन के प्रकरण में प्रत्येक उत्तराधिकारी को हस्तांतरण के लिए राशि रु. 10,000 (रुपये दस हजार) का सांकेतिक हस्तांतरण शुल्क देय होगा। ऐसा विभाजन मूल अनुमोदित भूखण्ड में केवल एक बार मान्य होगा अर्थात् मूल भूखण्ड दो से अधिक भूखण्डों में विभाजित किया जाना किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। शेष सभी प्रावधान यथावत रहेंगे।) किन्तु ऐसा समर्पण केवल एक अतिरिक्त इकाई की स्थापना हेतु ही किया जा सकेगा अर्थात् इन नियमों के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा भूखण्ड के अनुमोदित मानचित्र में वर्णित भूखण्ड को मात्र एक बार का विभाजन मान्य किये जाने की अनुमति होगी। अनुमोदित भूखण्ड को उसे किसी भी दशा में एक से अधिक टुकड़ों में विभाजन कर समर्पित किये जाने एवं पुनर्आबंटन की अनुमति नहीं होगी। समर्पण पश्चात् सृजित होने वाले नवीन भूखण्ड पर स्थापित होने वाली इकाई को समर्पित भूमि के परिप्रेक्ष्य में निष्पादित होने वाले पट्टा अभिलेख (नवीन इकाई) में वर्णित सभी नियमों व शर्तों तथा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन उसी प्रकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिस प्रकार नवीन आबंटन प्राप्तकर्ता इकाई से अपेक्षित होता है।”

- (चार) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 की कंडिका 3.4.1 की उप कंडिका क्रमांक 3.4.1.2 की बिन्दु क्रमांक-(अ) स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

कंडिका क्र. 3.4.1.2 - पति/पत्नि, रक्त संबंधियों एवं विधिक उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण—

- (अ) मूल आबंटी/मूल आबंटियों के पति/पत्नि एवं रक्त संबंधियों माता-पिता/पुत्र-पुत्री/भाई-बहन/पोता-पोती/नाती-नातिन एवं विविध उत्तराधिकारियों को आबंटित भूमि, शेड-भवन की लीज हस्तांतरित किये जाने पर हस्तांतरण/विभाजन के समय केवल प्रत्येक विभाजन प्राप्तकर्ता के लिए रुपये 10,000 (रुपये दस हजार) के सांकेतिक हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगा, (नियमानुसार अनुमोदित मूल भूखंड में मात्र एकबार विभाजन मान्य होगा, मूल भूखण्ड विभाजन हेतु इन नियमों में अन्यथा वर्णित सभी प्रावधान यथावत लागू होंगे) परंतु आबंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार निवेश, वस्तुओं के उत्पादन, आवृत्त क्षेत्र के निर्माण आदि कार्यवाही पूर्ण न होने पर यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

परंतु, यह भी कि उक्तानुसार हस्तांतरण की अनुमति मूल आबंटी/मूल आबंटियों द्वारा आवेदन जमा करने के समय शपथ-पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में दिये गये नामांकन के आधार पर दी जा सकेगी।

- (पांच) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 की कंडिका 3.4 की उप कंडिका क्रमांक 3.4.2.11 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :—

कंडिका क्र. 3.4.2.11 - सिक्कुरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल असेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्कुरिटीज़ इन्ट्रेस्ट एक्ट (सर्फेसी एक्ट) के प्रकरणों में भी भू-हस्तांतरण शुल्क तत्समय लागू प्रब्याजी के 10 प्रतिशत के बराबर देय होगी।

- (छः) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 की कंडिका 3.8 एवं इसकी उप कंडिकाओं क्रमांक 3.8.1, 3.8.2 एवं 3.8.3 को निम्नानुसार त्रुटिसुधार कर प्रतिस्थापित किया जाता है :—

कंडिका क्र. 3.8 - अभ्यावेदन —

- 3.8.1 इन नियमों के अंतर्गत आबंटन अधिकारी द्वारा पारित/जारी निरस्तीकरण आदेश अथवा किसी अन्य आदेश से असंतुष्ट पट्टेदार, ऐसा आदेश पारित होने की दिनांक से तीस (30) दिवस की अवधि में इस नियम की कंडिका (3.8.3) में वर्णित अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन निम्नानुसार अभ्यावेदन शुल्क सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा :—

क्रमांक	उद्योग की श्रेणी	अभ्यावेदन शुल्क (राशि रुपये में)	
		अभ्यावेदन	अभ्यावेदन
1.	सूक्ष्म, लघु उद्योगों हेतु	2000	--
2.	सूक्ष्म, लघु उद्योगों से भिन्न उद्योगों हेतु	10,000	--

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के विकास केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों के संबंधित अभ्यावेदन प्रकरणों में अभ्यावेदन शुल्क उस निगम को देय होगा।

- 3.8.2 अभ्यावेदन शुल्क वापिस नहीं होगा तथा निर्धारित अभ्यावेदन शुल्क के बिना जमा की गई अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। निर्धारित अभ्यावेदन शुल्क के बिना प्राप्त अभ्यावेदन प्रकरणों में यह माना जायेगा कि इकाई ने अभ्यावेदन नहीं किया है तथा तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही का अधिकार विभाग के अधिकारियों को होगा।

परंतु, निर्धारित अभ्यावेदन शुल्क के बिना प्राप्त अभ्यावेदन प्रकरणों में कोई कार्यवाही करने के पूर्व आवेदन अभ्यावेदक को कारण बताते हुये मूलतः वापिस कर दिया जायेगा।

3.8.3 अभ्यावेदन के संबंध में क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा —

क्रमांक	निरस्तीकरण आदेशकर्ता	अभ्यावेदन निराकरण अधिकारी
1	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सी.एस.आई. डी.सी.	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/सी.एस.आई. डी.सी.
2	अपर संचालक उद्योग संचालनालय	अपर संचालक उद्योग संचालनालय
3	संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय	संचालक/आयुक्त, उद्योग संचालनालय
4	कार्यपालक संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	कार्यपालन संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
5	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड.

(सात) उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 की कंडिका 2.2 के परिशिष्ट-1 में निम्नानुसार त्रुटिसुधार किया जाता है, अर्थात :—

नियमावली के परिशिष्ट-1 के बिन्दु क्रमांक (2) सहायक (अनुशांगिक) प्रयोजन हेतु, में वर्णित तालिका-स, में क्रमांक-4 के पश्चात् क्रमांक 10, 11 एवं 12 के स्थान पर 5, 6 एवं 7 पढ़ा जावे.

उपरोक्त सभी संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 मार्च 2021

क्रमांक एफ 05-01/2021/43.—राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10-05-2007 में संशोधन करते हुए जिला स्तरीय समीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार करता है :—

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | माननीय जिला प्रभारी मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य | उपाध्यक्ष |
| 3. | संबंधित जिले के केन्द्र एवं राज्य के मान. मंत्री, जिले के समस्त सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं बीस सूत्रीय कार्यालय के संबंधित कार्यालय प्रमुख. | सदस्य |
| 4. | जिला कलेक्टर | सदस्य सचिव |
| 5. | 10 अशासकीय सदस्य | नामांकित सदस्य |

2. नामांकित सदस्यों का नामांकन शीघ्र किया जायेगा.
3. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के यू.ओ. क्रमांक 66/सा.प्र.वि./2021/5, दिनांक 12-03-2021 द्वारा सहमति प्राप्त की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 अप्रैल 2021

क्रमांक एफ 5-01/2021/30/सं.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद) सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कलेक्टर कार्यालय	No Objection Certificate (NOC) for Movie shooting Registration/Renewal Application in and around State Protected Monuments	30 कार्य दिवस	कलेक्टर अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर	संभाग आयुक्त	संचालक संस्कृति

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 मई 2021

क्रमांक एफ 5-01/2021/30/सं.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), समक्ष अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कलेक्टर कार्यालय	No Objection Certificate (NOC) for Movie Shooting Registration/Renewal Application in the district	30 कार्य दिवस	कलेक्टर अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर	संभाग आयुक्त	संचालक संस्कृति

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 मई 2021

क्रमांक एफ 5-01/2021/30/सं.—राज्य शासन एतद्वारा फिल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य शासन के अधीन जिले के कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है। उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निशुल्क प्रदाय किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 23 मार्च 2021

क्रमांक/1693/A/02अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	चमारी प.ह.नं. 44	2.251	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कबीरधाम.	सरईपतेरा व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 11 जनवरी 2021

क्रमांक 01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बेमेतरा
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-धनेली, प.ह.नं.-40
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
641	0.08
योग	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धनेली जलाशय के डुबान क्षेत्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 3 अप्रैल 2021

क्रमांक 618/प्र.3/भू-अर्जन/अ-82/2021.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बेमेतरा
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-जेवरा, प.ह.नं.-39
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
639	0.04
650/1	0.12
650/2	0.03
653/1	0.03
653/2	0.03
653/3	0.02
653/4	0.02
653/5	0.02
653/6	0.03
686/1	0.02
686/2	0.02
686/3	0.02
687	0.05
688/2	0.04
688/3	0.01
688/4	0.02
734/1	0.03
734/2	0.01
734/8	0.04
737	0.04
765	0.05
766/1	0.02
योग	0.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवनाथ उद्वहन सिंचाई योजना के नहर विस्तार.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव अनंत तायल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 21 अप्रैल 2021

क्रमांक/6192/अधीक्षक/2021.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का आदेश क्र./ई 1-01/2021/एक-2, नवा रायपुर दिनांक 21-04-2021 के द्वारा श्री अभिषेक शर्मा, भा.प्र.से. (2018) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा जिला कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सहायक कलेक्टर कोरबा के पद पर पदस्थ किया गया है।

अतः प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टिकोण से कार्यालयीन आदेश क्र./15778/अधीक्षक/2020, कोरबा दिनांक 03-12-2020 में आंशिक संशोधन करते हुए शासन के उक्त आदेश दिनांक 21-04-2021 के परिपालन में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार प्रभार सौंपा जाता है।

क्र.	अधिकारी का नाम	सौंपे गए कार्य का विवरण
1.	श्री अभिषेक शर्मा, भा.प्र.से. (2018), सहायक कलेक्टर, कोरबा.	<p>प्रभारी अधिकारी :—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सिटी मजिस्ट्रेट ● सार्वजनिक उपक्रमों से समन्वय संबंधी कार्य <p>नोडल अधिकारी :—</p> <ul style="list-style-type: none"> ● नगर एवं ग्राम निवेश. ● (जिला शहरी विकास अभिकरण) डूडा. ● परिवहन विभाग ● जिला पंजीयक ● उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं ● समाज कल्याण विभाग एवं दिव्यांग ● औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ● जल संसाधन विभाग ● कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
2.	श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर.	<ul style="list-style-type: none"> ● अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी कटघोरा का दायित्व. ● कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.
3.	श्री आशीष देवांगन, रा.प्र.से. डिप्टी कलेक्टर.	<p>प्रभारी अधिकारी :—</p> <p>लायसेंस शाखा/शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण से संबंधित नस्ती स्वीकृति हेतु नोडल अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुतीकरण एवं आदेश दिनांक 03-12-2020 को सौंपे गये दायित्व.</p>

श्री अभिषेक शर्मा (भा.प्र.से.), सहायक कलेक्टर की मुख्यालय में अनुपस्थिति/अवकाश अवधि में श्री आशीष देवांगन, डिप्टी कलेक्टर लिंक अधिकारी रहेंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

हस्ता./-
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छत्तीसगढ़)

महासमुन्द, दिनांक 17 मार्च 2021

क्रमांक/55/बंधक श्रम/2021.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 2 के अनुसार राजस्व जिला महासमुन्द के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम व पद नाम (2)	समिति में पद (3)
1.	अपर कलेक्टर, महासमुन्द	अध्यक्ष
2.	जिले में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य	
	1. श्री गिरधर आंवडे ग्राम-भोरिंग, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला-महासमुन्द	सदस्य
	2. श्री रामजी ध्रुव ग्राम-सरेकेल विकासखण्ड महासमुन्द, जिला-महासमुन्द	सदस्य
3.	जिले में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता	
	1. श्री बबलू हरपाल वार्ड क्र. 06 महासमुन्द, जिला-महासमुन्द	सदस्य
4.	जिले में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अधिकरणों के प्रतिनिधि	
	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द	सदस्य
	2. उप संचालक, कृषि विभाग, महासमुन्द	सदस्य
	3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला-महासमुन्द	सदस्य
	4. श्रम पदाधिकारी, जिला-महासमुन्द	सदस्य/सचिव
5.	जिले में वित्तीय और ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि	
	1. अग्रणी बैंक प्रबंधक, महासमुन्द	सदस्य

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनिन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

- I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.
- II. ईट भट्टों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पारवलूम, काटन हैण्डलूम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी.
- III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.
- IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.
- V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिये पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.

- VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है।
- VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है, जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था।
- VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है।
- IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किये गये बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जायेगा।
3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3(1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुर्नगठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा।
4. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 7 के अनुसार अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार अभिलेख संधारित किया जायेगा :—
- I. विमुक्त बंधक श्रमिकों के नाम एवं पता संबंधित पंजी.
- II. विमुक्त बंधक श्रमिकों के पेशा, व्यवसाय एवं आय से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े से संबंधित पंजी.
- III. विमुक्त बंधक श्रमिकों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित पंजी, जिसमें आर्थिक सहायता, कृषि के लिए उपकरण प्रदाय, हस्तशिल्प या सहायक व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण, ऋण प्रदाय की जानकारी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदाय संबंधी जानकारी सम्मिलित हैं।
- IV. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (6), धारा 8 की उपधारा (2), धारा 9 की उपधारा (2), धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20 के अंतर्गत प्रकरणों का विस्तृत विवरण दर्शाने वाली पंजी.
5. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी।

महासमुंद, दिनांक 26 मार्च 2021

क्रमांक/56/बंधक श्रम/2021.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग महासमुन्द, जिला महासमुन्द के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम व पद नाम (2)	समिति में पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, महासमुन्द	अध्यक्ष
2.	अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य	
	1. श्री पूनाराम धृतलहरे, ग्राम-अछोला, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला-महासमुन्द	सदस्य
	2. श्री खिलावन ध्रुव ग्राम-सिनोधा, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला-महासमुन्द	सदस्य

(1)	(2)	(3)
3.	अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता	
1.	श्री रेखराज पटेल, ग्राम-धनसुली, विकासखण्ड महासमुन्द, जिला-महासमुन्द	सदस्य
4.	अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अधिकरणों के प्रतिनिधि	
1.	अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) महासमुन्द	सदस्य
2.	थाना प्रभारी, महासमुन्द	सदस्य
5.	अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि	
1.	शाखा प्रबंधक देना बैंक, महासमुन्द	सदस्य
6.	अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी	
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत महासमुन्द	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

- I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाइट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.
- II. ईंट भट्टों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पारवलूम, काटन हैण्डलूम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी.
- III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.
- IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.
- V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिये पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.
- VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.
- VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है, जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.
- VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.
- IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किये गये बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकर्ता समझा जायेगा.

3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3(1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा।

4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी।

महासमुंद, दिनांक 26 मार्च 2021

क्रमांक/57/बंधक श्रम/2021.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग बागबाहरा, जिला महासमुंद के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम व पद नाम (2)	समिति में पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बागबाहरा	अध्यक्ष
2.	अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य 1. श्री फूलसिंह ध्रुव वार्ड क्र. 02 नगर पालिका बागबाहरा	सदस्य
3.	अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता 1. श्री भूपेन्द्र (मुन्गू) ठाकुर वार्ड क्र. 07 नगर पालिका बागबाहरा	सदस्य
4.	अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अधिकारियों के प्रतिनिधि 1. अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), बागबाहरा 2. थाना प्रभारी, बागबाहरा	सदस्य सदस्य
5.	अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि 1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक बागबाहरा	सदस्य
6.	अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बागबाहरा	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

- I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाइट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा।
- II. ईंट भट्टों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पारवलूम, काटन हैण्डलूम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी।

- III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.
 - IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.
 - V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिये पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.
 - VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.
 - VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है, जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.
 - VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.
 - IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किये गये बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जायेगा.
3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3(1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुर्नगठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.
4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

महासमुंद, दिनांक 26 मार्च 2021

क्रमांक/58/बंधक श्रम/2021.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग पिथौरा, जिला महासमुंद के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम व पद नाम (2)	समिति में पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पिथौरा	अध्यक्ष
2.	अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य	
	1. श्री दुरपत व्यास पिथौरा	सदस्य
	2. श्री राजेश सिदार पिथौरा	सदस्य
3.	अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता	
	1. श्री अजय नंद पिथौरा	सदस्य

(1)	(2)	(3)
4.	अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अधिकारियों के प्रतिनिधि 1. अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) पिथौरा 2. थाना प्रभारी, पिथौरा	सदस्य सदस्य
5.	अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि 1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, पिथौरा	सदस्य
6.	अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा	सदस्य/सचिव
2.	<p>उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :-</p> <p>I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाइट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.</p> <p>II. ईंट भट्टों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पारवलूम, काटन हैण्डलूम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी.</p> <p>III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.</p> <p>IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.</p> <p>V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिये पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.</p> <p>VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.</p> <p>VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है, जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.</p> <p>VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.</p> <p>IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किये गये बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जायेगा.</p>	
3.	<p>बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3(1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.</p>	

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुर्नगठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.

4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

महासमुंद, दिनांक 26 मार्च 2021

क्रमांक/59/बंधक श्रम/2021.—बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग सरायपाली जिला महासमुन्द के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है :—

क्र. (1)	नाम व पद नाम (2)	समिति में पद (3)
1.	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सरायपाली	अध्यक्ष
2.	अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित सदस्य	
	1. श्री बुढान सिंह सिदार सरायपाली	सदस्य
	2. श्री सुशील दीवान सरायपाली	सदस्य
3.	अनुविभाग में निवासरत सामाजिक कार्यकर्ता	
	1. श्री टिकेश्वर पटेल सरायपाली	सदस्य
4.	अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय या अशासकीय अधिकरणों के प्रतिनिधि	
	1. अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), सरायपाली	सदस्य
	2. थाना प्रभारी, सरायपाली	सदस्य
5.	अनुविभाग में स्थित वित्तीय और ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि	
	1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, सरायपाली	सदस्य
6.	अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी	
	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बसना	सदस्य
	2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सरायपाली	सदस्य/सचिव

2. उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरुद्ध तमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-10-2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :—

- I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा.
- II. ईट भट्टों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पारवलूम, काटन हैण्डलूम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी.

- III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का समुचित रूप से क्रियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी.
 - IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करेगी.
 - V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिये पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यों का समन्वय करेगी.
 - VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है.
 - VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है, जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था.
 - VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है.
 - IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किये गये बंधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जायेगा.
3. बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3(1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अंतर्गत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेंगे.
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15-10-2012 के अनुसार समिति का पुनर्गठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जावेगा.
4. प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी.

डोमन सिंह,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur the 22nd March 2021

No. 260/Confdl./2021/II-1-2/2021.—It is hereby notified that pursuant to Notification bearing Nos. K. 13016/02/2020-US.II and K. 13016/03/2020-US.II dated 19th March, 2021 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Narendra Kumar Vyas and Hon'ble Shri Justice Naresh Kumar Chandravanshi respectively have assumed charge of the office of Additional Judge of the Chhattisgarh High Court in the Forenoon of March 22, 2021.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
DEEPAK KUMAR TIWARI, Registrar General.

Bilaspur the 25th March 2021

No. 73/I & E/2021.—Shri Sanjay Kumar Soni, Member of Lower Judicial Service, was suspended vide Registry Order No. 08/Comp./2015 dated 05th May, 2015 in contemplation of the departmental enquiry against him.

Hon'ble the High Court of Chhattisgarh as Disciplinary Authority hereby revokes the above suspension order and reinstate Shri Sanjay Kumar Soni, Member of Lower Judicial Service (presently placed under suspension with headquarter at Kawardha). His posting order will be issued separately.

By order of the High Court,
SANJAY KUMAR JAISWAL, Registrar (I & E)
